तालिका 1—भारत की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में प्रयुक्त विकास मॉडल, प्राथमिकताएँ, विकास दर का लक्ष्य एवं वास्तविक विकास दर प्रतिशत में

क्र. सं.	पंचवर्षीय योजनाएँ	प्रयुक्त विकास मॉडल	प्राथमिकताएँ	विकास दर का लक्ष्य	वास्तविक विकास दर (1980-81 के मूल्यों के आधार पर)
1.	प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56)	हैरोड-डोमर मॉडल	कृषि विकास व असन्तुलन दूर करना	2%	3.6%
2.	द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61)	महालनोबिस मॉडल	उद्योग व खनिज का विकास	4.5%	3.9%
3.	तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-66)	जॉन लैग्डो एवं एस. चक्रवर्ती मॉडल	कृषि, सिंचाई, उद्योग, खनिज का विकास	4.6%	2.3%
4.	चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74)	सामंजस्यता मॉडल ऐलन मान्ने व अशोक रुद मॉडल	स्थिरता के साथ विकास, औद्योगीकरण, ऊर्जा का विकास	5.7%	3.3%
5.	पंचम पंचवर्षीय योजना (1974-78)	योजना आयोग के दृष्ट योजना विभाग द्वारा निर्मित प्रारूप	गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना	5.5% प्रस्तावित संशोधित 4.4%	4.9%
6.	छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85)	संरचनात्मक परिवर्तन एवं वृद्धि पर बल देने की युक्ति पर आधारित	ऊर्जा, परिवहन, संचार, कृषि व उद्योग, सिंचाई	5.2%	5.4%
7.	सप्तम पंचवर्षीय योजना (1985-90)	दीर्घकालिक विकास युक्ति व उदारीकरण पर जोर देने पर आधारित मॉडल	गरीबी दूर करना, उत्पादकता, रोजगार में वृद्धि	5%	5.8%
8.	आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97)	उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में परिणत जॉन डब्ल्यू. मिलर मॉडल	मानव संसाधन का विकास अर्थात् जनसंख्या, शिक्षा, रोजगार आदि में	5.6%	6.8%
9.	नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002)	योजना आयोग के अध्यक्ष मधु दण्डवते प्रारूप पर आधारित	न्यायपूर्ण वितरण व समानता के साथ विकास	7%	6.5%
10.	दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07)	शोम-समिति द्वारा निर्धारित प्रारूप	मानव विकास, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, सामाजिक-आर्थिक उन्नति।	8%	—

भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य उद्देश्य

किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही कोई योजना बनायी जाती है लेकिन पंचवर्षीय योजना किसी देश के आर्थिक विकास से सम्बन्धित होती है, अतः इसके उद्देश्यों को दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक उद्देश्यों में विभाजित किया जा सकता है। एक योजना से दूसरी योजना के बीच दीर्घकालिक उद्देश्यों में कोई विशेष अन्तर नहीं होता, लेकिन अल्पकालिक उद्देश्यों में काफी अन्तर होता है। दीर्घकालिक उद्देश्य सामान्य होते हैं, जबकि

Scanned with CamScanner

अल्पकालिक उद्देश्य विशिष्ट होते हैं। 50 वर्षों तक विभिन्न योजनाओं के दीर्घकालिक उद्देश्य निम्नलिखित रहे हैं—

(1) उत्पादन को अधिकतम संभव सीमा तक बढ़ाना जिससे कि राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय के उच्च स्तर को प्राप्त किया जा सके।

(2) पूर्ण रोजगार प्राप्त करना।

(3) आय तथा सम्पत्ति की असमानता तथा आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण को कम करना।

इन्हें मुख्य उद्देश्य माना जा सकता है। संक्षेप में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्यों को योजनावार अधोलिखित प्रारूप में देखा जा सकता है—

प्रथम पंचवर्षीय योजना, 1951-56
(First Five Year Plan : 1951-56)

प्रथम योजनावधि (1951-56) तक की थी। यह योजना **हैरोड-डोमर** के मॉडल पर आधारित थी। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

लक्ष्य—1. द्वितीय विश्वयुद्ध और देश विभाजन से क्षतिग्रस्त अर्थव्यवस्था का पुनरुत्थान।

2. खाद्यान्न संकट का समाधान।

3. स्फीतिकारी प्रवृत्तियों को रोकना।

4. आर्थिक उपरिव्यय अर्थात् सड़कें बनाना, रेलों के इंजन तथा अन्य सामान का प्रतिस्थापन करना एवं सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं का विस्तार।

5. मूलभूत विकास-कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना।

6. ऐसी प्रशासनिक एवं अन्य संस्थानों का निर्माण करना जो विकास-कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हैं।

प्राथमिकताएँ (Priorities)—कृषि (Agriculture) को उच्चतम प्राथमिकता। कुल योजना का 31% आबण्टन। इसके बाद कुल परिव्यय का 27 प्रतिशत परिवहन तथा संचार पर व्यय किया गया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना, 1956-61
(Second Five Year Plan : 1956-61)

यह योजनावधि (1956-61) की रही। यह योजना अर्थशास्त्री **पी.सी. महालनोविस** के आगत-निर्गत मॉडल पर आधारित थी। चूँकि प्रथम योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी जा चुकी थी और कृषि लक्ष्य प्राप्त हो चुके थे इसलिए अब प्राथमिकताएँ और उद्देश्य बदले गये, जो कि इस प्रकार हैं—

लक्ष्य—(1) राष्ट्रीय आय में तीव्र वृद्धि।

(2) द्रुत औद्योगिकीकरण (Rapid Industrialization) को प्रोत्साहित करना और इनमें भी विशेष बल मूल एवं भारी उद्योग पर रहा।

(3) रोजगार अवसरों का सृजन।

(4) आय तथा सम्पत्ति की असमानताओं को कम करना और आर्थिक शक्ति का अधिक और समान वितरण।

प्राथमिकताएँ—प्राथमिकता के दृष्टिकोण से मूल एवं भारी उद्योगों के विकास की सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी तथा एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार की नींव का प्रयास रक्खा गया।

तृतीय पंचवर्षीय योजना, 1961-66
(Third Five Year Plan : 1961-66)

यह योजना **जॉन सैण्डी व एस.सी. चक्रवर्ती** मॉडल पर आधारित थी। इसके मुख्य लक्ष्य अधोलिखित हैं—

लक्ष्य—(1) राष्ट्रीय आय में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना।

(2) खाद्यान्न में आत्म-निर्भरता।

Scanned with CamScanner

(3) मूल-उद्योगों की क्षमता बढ़ाना ताकि भावी औद्योगीकरण की योजना पूरी हो सके।

(4) रोजगार के अवसरों का विस्तार।

प्राथमिकताएँ—इस योजना में कृषि, सिंचाई और संचालन शक्ति पर कुल व्यय के 36 प्रतिशत की व्यवस्था की गयी। यानी कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी, लेकिन मूल उद्योगों के विस्तार को भी आर्थिक विकास की दृष्टि से अनिवार्य समझा गया।

वार्षिक योजनाएँ, 1966-69
(Annual Plans : 1966-69)

तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक स्थिति बिगड़ने के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक दबाव पड़ा। वर्ष 1962 और 1965 में चीन और पाकिस्तान से युद्ध के कारण प्रतिरक्षा पर अधिक व्यय करना पड़ा, साथ ही वर्ष 1965-66 में सूखे की स्थिति से निबटने के लिए विदेशों से खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा। सूखे के कारण ऐसी उद्योगों के उत्पादन में कमी आ गयी जो अपने कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर थे। इन कारणों से कीमतें तेजी से बढ़ने लगीं और सरकारी कर्मचारियों द्वारा अदिक मँहगाई-भत्ते की माँग होने लगी। अत: प्रतिरक्षा और विकास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना का पुनर्गठन आवश्यक हो गया। इस योजना की तैयारी के बीच के वर्षों में वार्षिक योजनाएँ बनायी गयीं जिन पर तीन वर्षों में कुल 6,626 करोड़ रु. व्यय किये गये। तीनों वार्षिक योजनाओं का लक्ष्य अधोलिखित था—

लक्ष्य

(1) खाद्यान्न संकट का समाधान।

(2) युद्ध से उत्पन्न स्थितियों का निराकरण।

(3) मुद्रा-स्फीति पर नियन्त्रण।

(4) चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए आधार तैयार करना।

चौथी पंचवर्षीय योजना, 1969-74
(Fourth Five Year Plan : 1969-74)

ए.एस. मान और **अशोक रुद्र** मॉडल पर आधारित चौथी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं—

लक्ष्य—इस योजना के दो प्रमुख लक्ष्य रखे गये; पहला 'स्थिरता के साथ विकास' (Growth with stability) और दूसरा 'आत्म-निर्भरता' (Self-Reliance) की प्राप्ति।

उपर्युक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निम्न निर्णय लिये गये—

1. राष्ट्रीय आय की 5.5 प्रतिशत वार्षिक विकास-दर प्राप्त करना।
2. आर्थिक-स्थिरता कायम करना यानी खाद्यान्नों की कीमतों और सामान्य कीमत-स्तर को स्थिर रखना।
3. आत्म-निर्भरता प्राप्त करना।
4. सामाजिक आय और समानता प्राप्त करना। अर्थात् आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण को कम करना।
5. रोजगार और राष्ट्रीय न्यूनता प्राप्त करना।

प्राथमिकताएँ—न्यायपूर्ण तथा अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का सन्तुलित विकास, औद्योगिक विकास की गति को तेज करना, जिसमें आधारभूत और भारी उद्योगों पर विशेष बल दिया गया।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, 1974-79
(Fifth Five Year Plan : 1974-79)

लक्ष्य—समष्टि भावी + आगत-निर्गत + उपयोग पर आधारित पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दो प्रमुख लक्ष्य थे—

(अ) गरीबी उन्मूलन (Removal of Poverty)।

(ब) आत्म-निर्भरता (Self-Reliance)।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की विकास-विधि के मुख्य तत्व निम्नलिखित थे—

(1) कुल राष्ट्रीय उत्पाद में 5.5. प्रतिशत की सामान्य वार्षिक वृद्धि।

Scanned with CamScanner

(2) उत्पादक रोजगार के अवसरों का विस्तार।

(3) न्यूनतम आवश्यकताओं का राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसमें प्राथमिक शिक्षा, पीने का पानी, ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा, पौष्टिक भोजन, भूमिहीन श्रमिकों के मकानों के लिए जमीन, ग्राम सड़कें, ग्रामों का विद्युतीकरण और गन्दी बस्तियों की उन्नति और सफाई शामिल है।

(4) सामाजिक कल्याण का विस्तृत कार्यक्रम।

(5) कृषि, कुंजी तथा मूल उद्योगों और जनोपभोग (Mass consumption) के लिए वस्तुएँ उत्पन्न करने वाले उद्योगों पर बल।

(6) अनावश्यक उपभोगों पर कड़ा प्रतिबन्ध।

(7) निर्धन वर्गों को उचित स्थिर मूल्यों पर आवश्यक उपभोग की वस्तुएँ उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त वसूली एवं वितरण प्रणाली।

(8) न्यायपूर्ण कीमत-मजदूरी आय नीति।

(9) सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय असमानताओं (Regional Inequalities) को कम करने के संस्थान, राजकोषीय और अन्य उपाय।

(10) तीव्र निर्यात-प्रोत्साहन (Export Promotion) और आयात-प्रतिस्थापन (Import-substitution) पर बल देना।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (Minimum Needs Programme)

यह कार्यक्रम पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में चालू किया गया था, जिसके प्रमुख अवयव थे—

(i) प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा, (ii) ग्राम-स्वास्थ्य, (iii) ग्राम-जल सम्भरण, (iv) ग्राम-विद्युतीकरण, (v) ग्रामीण भूमिहीनों के लिए मकान, (vi) शहरी गन्दी बस्तियों के पर्यावरण में सुधार योजना।

छठी पंचवर्षीय योजना, 1980-85
(Sixth Five Year Plan : 1980-85)

सन् 1977 में सत्तासीन होने पर जनता सरकार ने पाँचवीं योजना को एक वर्ष पहले ही समाप्त किया और 1979-80 की अवधि के लिए एक 'परिभ्रामिक योजना' (Rolling Plan) बनायीं, जिसे छठीं पंचवर्षीय योजना कहा गया दुर्भाग्यवश जनता सरकार गिरी और काँग्रेस फिर सत्ता में आयी। और छठी पंचवर्षीय योजना वर्ष 1980-85 प्रस्तुत हुई।

लक्ष्य—(1) अर्थव्यवस्था के विकास में वृद्धि तथा संसाधनों के प्रयोग में कुशलता और उत्पादकता में वृद्धि करना।

(2) आर्थिक एवं तकनीकी आत्म-निर्भरता (Technical Self-Reliance) प्राप्त करने के लिए आधुनिकीकरण की गतिविधियों को मजबूत करना।

(3) ऊर्जा के देशीय संसाधनों में विकास तथा उसके उपयोग में संरक्षण।

(4) गरीबी तथा बेरोजगारी के प्रभाव में कमी लाना।

(5) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम द्वारा समाज के कमजोर वर्ग का जीवन-स्तर सुधारना।

(6) क्षेत्रीय असमानताओं में कमी करना।

(7) स्वैच्छिक स्वीकृति के जरिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को आगे बढ़ाना।

(8) पर्यावरण संरक्षण तथा विकास के लक्ष्य के मध्य सामंजस्य स्थापित करना।

(9) विकास की प्रक्रिया में जनता के सभी वर्गों की सहभागिता को बढ़ावा देना।

(10) आय तथा सम्पत्ति की विषमताओं में कमी लाना।

प्राथमिकताएँ—यह योजना 15 वर्ष (1980-95) की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनायी गयी थी। योजना के आरम्भिक वर्षों में भुगतान सन्तुलन की खराब स्थिति थी, लेकिन योजना के अन्तिम वर्ष में इसमें आशाजनक सुधार हुआ। गरीबी एवं बेरोजगारी उन्मूलन के चार महत्वपूर्ण कार्यक्रम—IRDP, NREP, RLEGP और TRYSEM शुरू किये गये।

Scanned with CamScanner

सातवीं पंचवर्षीय योजना, 1985-90
(Seventh Five Year Plan : 1985-90)

दीर्घकालीन विकास युक्तियों पर आधारित सातवीं योजना के भीतर भारतीय योजना के आधारभूत लक्ष्य वृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्म-निर्भरता तथा सामाजिक न्याय के अंतर्गत्त तीन और उसमें उद्देश्य जोड़े गये ये थे—

(क) खाद्यान्न उत्पादनों में वृद्धि, (ख) रोजगार के अवसर बढ़ाना, (ग) और उत्पादकता बढ़ाना।

इसकी 12 मुख्य शर्तें इस प्रकार है—

1. गरीबी में कमी तथा अन्तर-वर्गीय, अन्तर-क्षेत्रीय और गाँव तथा शहरों के विषमताओं को बढ़ना।
2. उत्पादक रोजगारों को बढ़ाना।
3. खाद्यान्न में आत्म-निर्भरता।
4. शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषक-आहार, सफाई एवं आवास सुविधाओं का विकास।
5. निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी के जरिए आत्म-निर्भरता की ओर बढ़ना।
6. छोटे परिवार के सिद्धान्त पर स्वेच्छा से अमल तथा सामाजिक/आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं के सकारात्मक भूमिका।
7. आधारभूत संरचना सम्बन्धी खामियों को दूर करना तथा उत्पादकता और स्थापित क्षमता के उपयोग में सुधार।
8. उद्योगों में प्रतिस्पर्द्धा, कुशलता और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना।
9. ऊर्जा की बचत और उसके गैर-परम्परागत स्रोतों का विकास।
10. योजना के विकेन्द्रीकरण और विकास में जनता की पूर्ण भागेदारी।
11. विकास-नियोजन की मुख्य धारा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का समन्वय।
12. पारिस्थितिकी (Ecological) और पर्यावरण संरक्षण तथा वानिकीकरण कार्यक्रम को प्रोत्साहन।

प्राथमिकताएँ—मानव संसाधन विकास, मुद्रा स्फीति पर नियन्त्रण रखते हुए रोजगार के अवसरों में वृद्धि, ऊर्जा संरक्षण और गैर-परम्परागत ऊर्जा-स्रोतों का विकास तथा जनसंख्या की वृद्धि-दर में कमी लाना इस आयोजन की प्रमुख प्राथमिकता थी। इस योजना में पहली बार विनियोजन में निजी क्षेत्र को वरीयता दी गयी कुल विनियोजन में से 48% सार्वजनिक क्षेत्र में तथा 52% निजी क्षेत्र में किया गया। गरीबी, बेरोजगारी एवं क्षेत्रीय असन्तुलन की समस्याओं पर सीधा प्रहार किया गया।

Scanned with CamScanner

ारों की आवश्यकता या सुधार नीतियों की पृष्ठभूमि

conomic Reforms or Background of Reform Policies)

पहली पंचवर्षीय योजना (अप्रैल, 1951) आरंभ करके भारत ने समाजवादी समाज तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था का मार्ग अपनाते हुए अपनी आर्थिक विकास की यात्रा आरंभ की थी। अब तक भारत दस पाँच-वर्षीय योजनाओं तथा पाँच एक-वर्षीय योजनाओं को पूरा कर चुका है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इन पाँच दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था को अनेक सफलताएँ प्राप्त हुई हैं, किंतु असफलताओं की संख्या भी कम नहीं है। योजनाओं की अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र को अत्यधिक महत्त्व दिया गया था। निजी क्षेत्र को अधिकतर सरकारी नियंत्रण में रखा गया। व्यापार तथा उद्योग पर कई प्रतिबंध लगाए गए थे। नौकरशाही तथा लाल-फीता शाही अर्थव्यवस्था के सामान्य लक्षण थे। कुल मिलाकर इनका परिणाम यह हुआ कि जून 1991 के अंत में देश में अभूतपूर्व

Scanned with CamScanner

आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। विदेशी मुद्रा के भंडार केवल दो सप्ताह के आयात के लिए पर्याप्त थे। नए ऋण प्राप्त नहीं हो रहे थे। अनिवासी भारतीयों (NRIs) के खातों से बड़ी-बड़ी राशियाँ निकाली जा रही थीं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भारतीय अर्थव्यवस्था से विश्वास उठ रहा था। औद्योगिक प्रगति विपरीत दिशा में जा रही थी और कीमतें आकाश को छू रही थी। अर्थव्यवस्था को आर्थिक संकट से निकालने और उसे तेजी से निरंतर विकास के मार्ग पर पुनः लाने के लिए, वित्तीय असंतुलन को दूर करने, महंगाई को नियंत्रण में लाने और भुगतान संतुलन को संतुलित करने तथा विदेशी मुद्रा के भंडारों में पुन:पूर्ति करने के लिए आर्थिक सुधार करना अत्यंत आवश्यक हो गया था। इस हेतु एक उपयुक्त आर्थिक नीति लागू करना अनिवार्य बन गया था। आर्थिक सुधारों या नई

Scanned with CamScanner

सन् 1991 से भारत सरकार ने देश को आर्थिक संकट से निकालने तथा विकास की गति को तेज करने के लिए विभिन्न आर्थिक सुधार आरंभ किए। ये सुधार निम्नलिखित तीन नीतियों के रूप में देखे जा सकते हैं:

(i) उद्योग और व्यापार के लिए ''लाइसेंसिंग'' (Licensing-L) के स्थान पर उदारीकरण (Liberalisation-L) की नीति।

(ii) उद्योगपतियों के लिए ''कोटा'' (Quota-Q) प्रणाली के स्थान पर निजीकरण (Privatisation-P) की नीति।

(iii) आयात तथा निर्यात के लिए ''परमिट'' (Permits-P) के स्थान पर वैश्वीकरण (Globalisation-G) की नीति।

इन सुधारों को प्रायः नई आर्थिक नीति (New Economic Policy) या LQP के स्थान पर LPG की नीति से संबोधित किया जाता है।

Scanned with CamScanner

5. विकास का उ.नि.वै. मॉडल

विकास का उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जो बड़े जोर-शोर से 1991 में चालू किया गया का मुख्य उद्देश्य विकास के लिए एक नई रणनीति अपनाना था जिसमें निजीकरण (Privatisation) और वैश्वीकरण (Globalisation) पर बल दिया जाए। देश के स्तर पर दो मुख्य परिवर्तन किए गए। प्रथम, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए गए। चाहे सरकार हानि-उठाने वाले सार्वजनिक उद्यमों को निजी क्षेत्र को सौंपना चाहती थी, किन्तु वह इस लक्ष्य

Scanned with CamScanner

में विफल रही क्योंकि इन्हें लेने वाले उद्यमों में अनिवेश (Disinvestment) आरम्भ कर दिया और इससे प्राप्त राशि को राजकोषीय घाटे (Fiscal deficits) को कम करने के लिए इस्तेमाल किया। अत: विभिन्न सामाजिक सीमाबन्धनों के कारण सरकार अपने निजीकरण के प्रोग्राम को लागू न कर पायी, चाहे यह अर्थव्यवस्था को निजी क्षेत्र-देशीय एवं विदेशी-के प्रति उदार बनाने में सफल हुई।

दूसरे, बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी क्षेत्र को औद्योगिक इकाइयां लगाने की इजाजत देकर सरकार ने वे बहुत-सी बेड़ियां जो निजी क्षेत्र के निवेश में रुकावट थीं या इसके निवेश में विलम्ब का कारण थीं, काट दीं।

तीसरे, एम. आर. टी. पी. कम्पनियों के संदर्भ में सरकार ने परिसम्पत्तियों (Assets) की सीमा को समाप्त करके व्यापारिक घरानों (Business houses) को स्वतन्त्र कर दिया कि वे एकाधिकार आयोग की अनुमति लिए बिना निवेश कर सकते हैं। जाहिर है कि विकास को प्रोन्नत करने का विचार सरकार के लिए अधिक महत्त्वपूर्ण था और साम्यता (Equity) के प्रश्न की अभी अनदेखी की जा सकती थी।

चौथे, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (Foreign Direct Investment) को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 51 प्रतिशत तक कर लेने की स्वीकृति का निर्णय किया। सरकार 51 प्रतिशत से अधिक विदेशी निवेश के प्रस्तावों पर भी विचार कर सकती है परन्तु ऐसे प्रस्तावों के लिए सरकार से पहले स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। विदेशी तकनीशियनों, देश में विकसित तकनालाजी के विदेशी परीक्षण के लिए कोई स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं होगी, भले इनके लिए मुआवजा दिया जाए।

पांचवें, जीर्ण रूप में बीमार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (Board of Industrial and Financial Reconstruction) के हवाले किया जाएगा ताकि वह इनके पुनरुत्थान/पुनर्वास सम्बन्धी योजनाएं तैयार करे। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए एक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली कायम की जाएगी ताकि पुनर्वास के उपायों द्वारा प्रभावित श्रमिकों को इनके दुष्प्रभाव से बचाया जा सके।

छठे, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निष्पादन को उन्नत करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबन्धकों और सरकारी कम्पनियों को बोर्डों को अधिक स्वायत्तता दी जाएगी और इन्हें अधिक व्यावसायिक (Professional) बनाया जाएगा।

अन्तिम, अन्य देशों से निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए अर्थव्यवस्था को खोल दिया जाएगा। विदेशी पूंजी, तकनालाजी और अन्य सम्बन्धित आयात को सुविधाजनक बनाने के लिए आयात-शुल्क तथा अन्य अवरोधक (Barriers) घटाए जाएंगे।

पूर्व-प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिंम्हा राव और पूर्व वित्त मंत्री डा. मनमोहन सिंह द्वारा चालू किए गए विकास के मॉडल में निजी क्षेत्र को एक बड़ा कार्यभाग अदा करने पर बल दिया गया है। इसमें हमारी विकास-प्रक्रिया में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की कहीं बड़ी मात्रा द्वारा पूर्ति की कल्पना की गयी है। इसमें निर्यात-प्रेरित विकास (Export-led growth) की रणनीति अपनायी जाएगी और पहले चल रहा आयात प्रतिस्थापन रणनीति (Import substitution strategy) का परित्याग किया जाएगा। इसमें सरकार के कार्यभाग को महत्त्वपूर्ण रूप में कम किया जाएगा और इस प्रकार बुनियादी रूप में आयोजन (Planning) का परित्याग करके अधिक उदार और बाजार-प्रेरित विकास का ढांचा कायम किया जाएगा।

आलोचकों ने उ.नि.वै. विकास-मॉडल में कुछ बुनियादी कमजोरियों का संकेत दिया है।

पहला, इसका केन्द्र बहुत संकुचित है क्योंकि यह मुख्यत: निगम क्षेत्र (Corporate sector) तक सीमित है जो कि कुल देशीय उत्पाद में केवल 10 प्रतिशत का योगदान देता है। दूसरे, इस मॉडल में कृषि तथा अन्य कृषि-आधारित उद्योगों की उपेक्षा की गयी है जो कि जनता के लिए रोजगार-जनन का मुख्य स्रोत हैं। तीसरे, उपभोग वस्तु क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय निगमों (Multinationals) के प्रवेश की स्वीकृति देकर इस मॉडल ने लघु क्षेत्र में उपभोग वस्तुओं का उत्पादन करने वाले छोटे उद्यमियों के हितों पर करारी चोट की है। यदि बहुराष्ट्रीय निगमों का बेरोक-टोक प्रवेश जारी रहता है, तो इससे लघु-क्षेत्र में श्रम-विस्थापन (Labour displacement) का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। चौथे, इसमें सन्देह नहीं कि निर्यात प्रोन्नत हुए हैं परन्तु आयात को सुविधाजनक बनाने की नीति के अधीन सरकार ने आयात-खिड़की को बहुत ही ज्यादा खोल दिया है और इसके नतीजे के तौर पर बढ़ते हुए निर्यात के लाभ अपेक्षाकृत और तेज रफ्तार से बढ़ते आयात से निष्प्रभावी हो गए और इस प्रकार व्यापार-घाटा बढ़ गया है। अब इस बात पर लगभग सहमति प्राप्त हो गयी है कि बहुराष्ट्रीय निगमों के अन्धाधुन्ध प्रवेश को रोकना चाहिए, विशेषकर उपभोग वस्तु क्षेत्र में और ऐसे क्षेत्रों में जिनमें देशीय सामर्थ्य विकसित हो चुकी है अन्तिम, इस मॉडल में विकास के पूंजी-प्रधान ढांचे की कल्पना की गयी है और इसके रोजगार-क्षमता बढ़ाने के बारे में गंभीर सन्देह है। यह कहा जा रहा है कि इसके कारण अल्पकाल में बेरोजगारी हो जाएगी परन्तु दीर्घकाल में यह इस समस्या का समाधान कर लेगा। परन्तु दीर्घकाल की अवधि कितनी लम्बी होगी, इसका कोई संकेत नहीं दिया गया।

Scanned with CamScanner